ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. No.- 308-309

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

समृद्ध और सशक्त होता उत्तर प्रदेश

प्रो0 राम कृष्ण उपाध्याय

निदेशक– पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया,
सह अध्यक्ष– अर्थशास्त्र विभाग, कुँवर सिंह स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बलिया (उ0प्र0), भारत

Received-17.03.2023, Revised-24.03.2023, Accepted-29.03.2023 E-mail: dr.ramkrishna1975@gmail.com

सारांशः उत्तर प्रदेश एक ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था की तरफ अग्रसर है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए प्रदेश सरकार विभिन्न प्रयास कर रही है । यह पेपर उन्हीं प्रयासों का तीन पहलुओं पर एक समीक्षा है।

कुंजीभूत शब्द– अर्थव्यवस्था, सामाजिक कल्याण , आर्थिक प्रगति , पर्यावरणीय अर्थव्यवस्था, आर्थिक प्रगति, हस्तांतरण

विकास की अलग–अलग अवधारणाऐ हैं और परिणामस्वरुप विषय के प्रति अलग–अलग दृष्टिकोण हैं। हालाँकि, सभी दृष्टिकोण विकास और शासन के बीच सम्बन्ध से सम्बंधित हैं। विकास में आर्थिक, सामाजिक, राजनितिक, लिंग, सांस्कृतिक, धार्मिक और पर्यावरणीय कारकों सहित असंख्य चर शामिल हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार ने फरवरी 2023 में अपना बजट प्रस्तुत किया है। जिसकी समीक्षा आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यावरणीय स्तर पर निम्न है।

आर्थिक– देश की जीडीपी में प्रदेश का योगदान 08 प्रतिशत से अधिक का है । वर्ष 2021–22 में प्रदेश के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी०एस०डी०पी०) में १६.८ प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी जो देश की विकास दर से अधिक रही । वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह जिक्र किया है कि, "वर्ष 2017 से पूर्व, प्रदेश की बेरोजगारी दर 14.4 प्रतिशत थी, आज यह घटकर लगभग 4.2 प्रतिशत हो गयी है।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण एवं शहरी के अंतर्गत आवास निर्माण, ग्रामीण स्वच्छ शौचालय निर्माण, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों की स्थापना, स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत 'इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड कांटेस्ट में तथा पी०एफ०एम०एस० पोर्टल द्वारा डी०बी०टी० के माध्यम से लाभार्थियों को धनराशि हस्तांतरण करने में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। दुग्ध उत्पादन, गन्ना एवं चीनी उत्पादन तथा एथेनोल की आपूर्ति में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है।

वर्तमान सरकार के अब तक के कार्यकाल में लगभग 21,६६६ किलोमीटर लम्बाई में ग्रामीण मार्गों का निर्माण किया जा चुका है तथा लगभग १८,४०७ किलोमीटर लम्बाई में मार्गों का चौडीकरण किया गया है। १८८ दीर्घ सेतु पहुँच मार्ग सहित पूर्ण किये गए हैं तथा ७४ रेल उपरिगामी सेतुओं का निर्माण कार्य पूर्ण कर आवागमन हेतु चालू किये जा चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2022–23 में प्रदेश के ६०,३६७ किलोमीटर लम्बाई की सड़कों को गड्ढामुक्त तथा १४,१४४ किलोमीटर लम्बाई के मार्गों को नवीनी.त किया गया।

प्रति व्यक्ति आय– वर्ष 2021–22 के त्वरित अनुमान के अनुसार प्रदेश की निवल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में प्रचलित भावों पर प्रतिव्यक्ति आय वर्ष 2011–12 के रू ३2002 से बढ़कर वर्ष 2020–21 व 2021–22 में क्रमशः रू ६१३७४ एवं रू ७०७८2 हो गयी है।

सामाजिक– प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने जन–जन के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाली व्यवस्था की नींव रखने के लिए भारतीय राजनीति में विकास की भूमिका को पुनः परन्तु नए तरीके से प्रस्तुत किया है। अर्थशास्त्र की भाषा में विकास के इस मॉडल के लिए मूल्य–स्तर में परिवर्तन की अपेक्षा प्रति व्यक्ति आय में निरंतर वृद्धि की आवश्यकता है, ताकि अन्त्योदय हो सके अर्थात समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से वंचित वर्ग तक विकास का लाभ पहुँचाया जा सके।

मोदी सरकार की इस दूरगामी दृष्टि से प्रेरणा लेते हुए योगी सरकार ने राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु एक समग्र योजना की अवधारणा और इसके क्रियान्वयन की व्यापक रणनीति तैयार की। योगी सरकार ने विकास की प्राथमिकता के साथ दलितों, शोषितों और वंचितों के उत्थान के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया है और इसके लिए नित नई योजनाओं का सृजन किया स 15 करोड़ अन्त्योदय और पात्र लोगों को निःशुल्क खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन किसी विकासशील देश के लिए भी कल्पनातीत होगा, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्णता के साथ लागू किया। एक ओर सामाजिक कल्याण के प्रति दृढ प्रतिबद्धता तो दूसरी ओर विदेशी निवेश के प्रति उत्साह, सरकार द्वारा अपनाए गए समाज के समग्र विकास के मूल मंत्र को प्रदर्शित करता है। उत्तर प्रदेश सरकार सामाजिक सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है तथा इसके लिए सरकार द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठावस्था पेंशन का प्रावधान किया गया है वहीं मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के माध्यम से विवाह और पथ विक्रेताओं को ऋण प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है।

श्रमिको के कल्याण हेतु भी सरकार वचनबद्ध है। श्रमिकों के बच्चों को निशुल्क गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देने हेतु प्रदेश

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-16, No.- I, Issues-27, YEAR- Jan.-March-2023

के प्रत्येक मंडल में एक–एक आवासीय विद्यालय की स्थापना की है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजनान्तर्गत अब तक लगभग 7 लाख लाभार्थियों का पंजीकरण किया जा चूका है। बाल श्रमिक विद्या योजना के तहत 2000 बच्चों को योजना से आच्छादित कर लाभ दिया जा रहा है। वैसे ही बहुत सारे ऐसी योजनायें है जिससे उत्तर प्रदेश सरकार वंचितों और दलितों को मदद कर रही है और उनको कार्यबल में शामिल कर रही है। कुछ वर्षों बाद उत्तर प्रदेश अत्यधिक कार्यबलों वाला प्रदेश हो जाएगा।

पर्यावरणीय– वृक्षों से ही भूमि संरक्षण, जल संरक्षण एवं पर्यावरण सुरक्षा सुनिश्चित होती है। वन, दुर्लभ प्रजातियों का प्रा.तिक वास है । प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण का कुल क्षेत्रफल 22,23६ वर्ग किलोमीटर है जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 2४०,६2८ वर्ग किलोमीटर के सापेक्ष मात्र ६.23 प्रतिशत है। प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण में वर्ष 2०1६ की तुलना में वर्ष 2०21 में ६1 वर्ग किलोमीटर के वृद्धि हुई है। यह वृद्धि मुख्य रूप से वनों के समुचित प्रबंधन तथा सफल वृक्षारोपण के कारण हुई है।

प्रदेश की विविधतापूर्ण भौगोलिक संरचना एवं जलवायु में पाए जाने वाले वन्य जीवों एवं जैव विविधता के संरक्षण हेतु प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव विहारों, आरक्षित संरक्षण क्षेत्र तथा प्राणी उद्यानों की स्थापना की गयी है। वन्य जीवों के प्रति जनमानस में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से जनपद गोरखपुर में शहीद अशफाक उल्लाह खान प्राणी उद्यान का निर्माण, इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी पार्क का विकास किया गया है। गौरैया व अन्य पक्षियों के प्रति जागरूकता हेतु प्रतिवर्ष 2० मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है।

निष्कर्ष– समृद्धि सकारात्मक सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालता है। विकास को ही उन्नति अथवा आर्थिक प्रगति के एकमात्र पैमाने के रूप में देखे जाने की कोशिशों को दशकों से विश्व स्तर पर चुनौती दी गई है। युद्ध के बाद के दशकों में यूरोपीय पुनर्निर्माण और उपनिवेश से बाहर आने वाले देशों, जिसे उस समय थर्ड वर्ल्ड अर्थात तीसरी दुनिया कहा जाता था, में विकास को लेकर यह सोच कि विकास केवल पूंजी निर्माण के माध्यम से ही हो सकता था, उस सोच को चुनौती दी गई और अब विकास में मानवीय चेहरा प्रमुख प्रतिमान में हो गया। समय के साथ, रोम की प्रलय के दिन की मान्यता को मानने वाले क्लब ने इस माल्थुसियन मत पर फिर से विचार किया कि मानवजनित हस्तक्षेपों के कारण प्रा.तिक संसाधनों की कमी भविष्य में मानव आर्थिक विकास की महत्वाकांक्षाओं को बनाए रखने में सक्षम नहीं होगी।

ऐसे में अनेक सम्मेलन, वैज्ञानिक आकलन और वैश्विक घोषणाएं हुई हैं, जो सहस्राब्दी विकास लक्ष्यों सहित विकास के लिए एक अधिक समग्र .ष्टिकोण को बढ़ावा देने की मांग करती हैं, और जिन्हें अंततः 2015 में एसडीजी द्वारा बनाई गई अधिक व्यापक कार्यसूची से प्रतिस्थापित किया गया है। 17 लक्ष्यों के माध्यम से विकासात्मक शासन के लिए एक पर्याप्त विस्तारित और व्यापक कार्यसूची प्रस्तुत करते हुए एसडीजी, अर्थशास्त्री मोहन मुनसिंघे के 'सस्टेनोमिक्स' में एक सैद्धांतिक आध ार पाते हैं, जो एक ट्रांसडिसप्लिनरी ज्ञान के आधार पर तैयार किया गया है। यह निर्माण आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लक्ष्यों को जोड़ता है, जिससे समानता, दक्षता और स्थिरता के तीन मानक उद्देश्यों को संबोधित किया जाता है। अतः जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में विस्तार करेगा वही सशक्त और समृद्ध होगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने इन तीनो क्षेत्रों में विस्तार किया है। अंतिम व्यक्ति तक के आर्थिक और सामाजिक कल्याण के संरक्षण और संवर्धन के उद्देश्य से संचालित विकासात्मक शासन, सरकार की सफलता के लिए अनिवार्य है। यह वास्तव में एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करता है। पुरे देश को 5 ट्रिलियन वाला अर्थव्यवस्था बनाने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह करने में सफल होगा।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, (2023, फरवरी), लखनऊः अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
2. खन्ना, स. क. (2023), बजट 2०23–2४, लखनऊ : वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
3. त्रिपाठी, अ. (2023), उत्तर प्रदेश की आर्थिक समीक्षा, लखनऊ : अर्थ एवं संख्या प्रभाग, नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश।
4. राय, आ. (2023, मार्च 25), समृद्धि की ओर अग्रसर उत्तर प्रदेश, वाराणसी, उत्तर प्रदेश, भारत : दैनिक जागरण।
5. रॉय, अ. श. (2022, September 13), आजादी का अमृत महोत्सव : भारत की विकास गाथा, विकासात्मक विरोधाभास और आर्थिक विकास की बदलती दृष्टि, Retrieved from orfonline.org: https://www.orfonline.org/hindi/research/azadi-ka-amrit-mahotsav-the-story-of-the-development-of-india-at-75/
6. श्रीवास्तव, ह. (2023, फरवरी 2७). 2०23–2४ में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में होगा 4 लाख करोड़ का इजाफा। लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत : हिंदुस्तान।

*****